आकाशवाणी

क्षेत्रीय समाचार एकांश

देहरादून (उत्तराखण्ड)

मंगलवार 08.07.2025

समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- केंद्र सरकार ने राज्य की लगभग तीन हजार 800 करोड़ रुपये की कृषि और बागवानी से जुड़ी योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मानसून के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
- बी०एस०एन०एल पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पुरानी तकनीक हटाकर नया नेटवर्क सिस्टम लगाएगा।
- विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में समग्र शिक्षा योजना के तहत एस०सी०ई०आर०टी में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

सैद्धान्तिक सहमति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर उत्तराखंड में कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग का अनुरोध किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्य की लगभग तीन हजार 800 करोड़ रुपये की योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी।

मुख्यमंत्री ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई प्रस्ताव रखे, जिनमें कृषि बाड़ निर्माण के लिए एक हजार बावन करोड़ रुपये, फार्म मशीनरी बैंक के लिए चार सौ करोड़, स्टेट मिलेट मिशन के तहत लगभग एक सौं पैंतीस करोड़, और बीज उत्पादन के लिए 5 करोड़ रुपये की योजनाएं शामिल हैं।इसके अलावा, सेब उत्पादन, विपणन और भंडारण, कीवी की खेती और वन्यजीवों से सुरक्षा, नवाचार व स्टार्टअप्स, तथा ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भी योजनाएं प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खेती, भूमि सर्वेक्षण, युवा प्रशिक्षण, एग्री टूरिज्म स्कूल और माइक्रोबायोलॉजी लैब जैसी योजनाओं पर भी चर्चा की। श्री धामी ने राज्य में कोल्ड स्टोरेज, नर्सरी, ग्रेडिंग यूनिट, और सुपर फूड्स से जुड़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भी सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे कार्यों की समय सीमा बढ़ाने और नए प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति देने का आश्वासन दिया।

पिटकुल बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मानसून के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं। सचिवालय में पिटकुल की समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लाइन ब्रेकडाउन की स्थिति में तुरंत विश्लेषण कर आपूर्ति बहाल की जाए और तय मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हो।

मुख्य सचिव ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लागत न बढ़ने की सख्त हिदायत दी। साथ ही कहा कि जो भी मास्टर प्लान तैयार हों, उन्हें लागू करने से पहले केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से समीक्षा जरूर कराई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद निर्माणाधीन बिजली संयंत्रों और सब–स्टेशनों का दौरा करेंगे।

बैठक में पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी.सी. ध्यानी ने बताया कि संस्था की रेटिंग 2024–25 में 'ए' से बढ़कर 'ए प्लस प्लस'' हो गई है। इससे मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को रियायती बिजली दरों के रूप में मिलेगा।

उन्होंने बताया कि एशियाई विकास बैंक की सहायता से चल रही छह परियोजनाएं– सेलाकुई, खटीमा, लोहाघाट, धौलाखेड़ा, आराघर और मंगलौर वर्ष 2026 तक पूरी हो जाएंगी। इससे कम वोल्टेज और बार–बार बिजली जाने की समस्याएं कम होंगी और उद्योगों व आम उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

पंचायत चुनाव

उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिन पंचायती चुनाव का माहौल है। इस बीच, पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने आम लोगों को कहा है कि पंचायत चुनाव के जरिए गांवों की सरकार बनाने का यह मौका है, इसलिए ईमानदार और कर्मठ जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था देश में जमीनी लोकतंत्र की मजबूत नींव है और गांवों के सशक्त विकास के लिए इसमें सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

मंत्री ने बताया कि हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायत चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई को होंगे, जबकि परिणाम 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न पदों के लिए 63 हजार 812 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर जागरूक है।

सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पंचायतों के विकास और अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निदेशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

नया नेटवर्क सिस्टम

बीएसएनएल अब पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में पुरानी तकनीक हटाकर नया नेटवर्क सिस्टम लगाएगा। इससे लोगों को तेज इंटरनेट और बेहतर कॉल की सुविधा मिलेगी। यह नया सिस्टम डीडीहाट, जौलजीबी, निगालपानी और धारचूला के फोन केंद्रों में लगाया जाएगा। इससे बैंकों के एटीएम और सेना से जुड़े कामों में भी मदद मिलेगी।

बीएसएनएल नैनीताल के उप महाप्रबंधक श्रीराम गौड़ ने बताया कि नई तकनीक से गांवों में संचार सुविधा पहले से बेहतर होगी।

शिलान्यास

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में समग्र शिक्षा योजना के तहत एससीईआरटी में आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा चार करोड़ तिहत्तर लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

निर्माण कार्य उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत टाइप–3 के तीन, टाइप–2 के दो और टाइप–5 का एक आवास बनाया जाएगा। डॉक्टर रावत ने प्रादेशिक शिक्षा संकुल परिसर, ननूरखेड़ा के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत बारह लाख रुपए से अधिक है।

तिथि स्थगन

मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड, राधा रतूड़ी ने हरिद्वार में होने वाली कांवड़ यात्रा के मद्देनज़र पुलिस विभाग और नगर निगम से संबंधित द्वितीय अपीलों व शिकायतों की सुनवाई की तिथियां स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय इन विभागों के अधिकारियों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

आयुक्त ने स्पष्ट किया कि हरिद्वार के वे विभाग जिनकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लगी है और जिनकी सुनवाई निर्धारित है, वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन माध्यम से हाइब्रिड मोड में अपना पक्ष रख सकते हैं।

यदि कोई अधिकारी ड्यूटी के कारण हाइब्रिड मोड में भी शामिल नहीं हो सकता, तो आयोग को ई–मेल के माध्यम से तिथि संशोधन का अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे मामलों में कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद नई सुनवाई तिथि निर्धारित की जाएगी।

तिथि संशोधन या जानकारी के लिए संबंधित कोर्ट स्टाफ से भी संपर्क किया जा सकता है। यह व्यवस्था अधिकारियों की सुविधा और यात्रा व्यवस्था में बाधा न आने के उद्देश्य से की गई है।

जनदर्शन

देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भूमि विवाद, सीमांकन, नगर निगम, एमडीडीए, शिक्षा, पुलिस और विधिक सहायता से जुड़ी कुल 125 शिकायतें दर्ज की गईं।

जिलाधिकारी ने सभी विभागों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और संबंधित को जानकारी देने के निर्देश दिए। महिला, बुजुर्ग और बच्चों से जुड़ी शिकायतों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने को कहा गया।

नगर निगम, तहसील, पुलिस और अन्य विभागों को लंबित प्रकरणों पर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

ब्रिक्स संगठन के घोषणा पत्र पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया को सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स व अमेरिका के बीच टैरिफ वार में उलझा भारत, शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है – टैरिफ युद्ध फिर शुरू : सात देशों पर 25 से 40 फीसदी शुल्क, ब्रिक्स देशों को भी धमकी।

नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखा है – केंद्र ने कृषि व बागवानी विकास के लिए तीन हजार 800 करोड की सहमति दी। दैनिक जागरण ने प्रदेश में खेती–किसानी की बदलेगी तस्वीर, केंद्र से मिलेंगे 3,800 करोड़ रुपए, शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया है।

प्रदेश में हाई एल्टीट्यूट अल्ट्रा मैराथन की तैयारियां की जा रही है। इस खबर पर अमर उजाला ने लिखता है – हर साल होगी हाई एल्टीट्यूट मैराथन।

उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा की खबर पर अमर उजाला लिखता है – 11 से भारी वाहनों के थमेंगे पहिए। समाचार पत्र के अनुसार 16 जुलाई तक दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर हल्के वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी। वाहनों को मेरठ सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। यह निर्णय कांवड यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि और किसी भी तरह के हादसे से बचाव के दृष्टिगत लगाया गया है।